की जो गतिविधि चलती हैं, वह कोई ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तानी ही यहां आकर करते हैं, वह तो खोजते हैं कि हमारा कौन एजेंट बन सकता है, किसको हम अपना एजेंट बना सकते हैं। इसलिए मदरसों के बारे में जो बात कही, इसी संदर्भ में आई। मुझे जम्मू-कश्मीर के लोगों ने भी यही बात कही, जो मुझे गुजरात में कही गई या राजस्थान में कही गई। उसी संदर्भ में उसका उल्लेख हुआ, किसी और संदर्भ में, मैं समझता हूं, अगर कोई करता है तो गलत करता है और मैं समझता हूं कि देश की अधिकांश जनता हिन्दू मुसलमान, देश के प्रति निष्ठा रखती है और देश की सुरक्षा के लिए वह भी उतनी ही चिंतित है, जितनी भारत सरकार है। इतना ही मुझे कहना है।

SHRI ADHIK SHIRODKAR: Mr. Chairman, Sir, recently there was an exhibition in Delhi and Mumbai of arms seized from ISI activities. They were highly successful. May I know from the hon. Minister whether the Government would consider bringing out a small documentary to show the same both in cinema theatres as well as on T.V. to acquaint the common man with the ISI activities and the manner in which the sophisticated methods of communication, destruction, etc., are used?

SHRI L.K. ADVANI: Mr. Chairman, Sir, this is not a question. This is a suggestion for action. I will certainly keep it in mind.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Death of Official in the Ministry of Mines

*141. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any progress has been made in the investigation of the circumstances which led to the death of Shri M.C. Mahapatra, Joint Secretary in the Ministry of Mines on September 27, 1997;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time by which the investigation is likely to be completed?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) Shri M.C. Mahapatra, posted as Joint Secretary in the Department of Mines, died on 27th September, 1997 after he had "fallen down" from Shastri Bhavan building. Delhi Police registered the case and took up the investigation. However, a request was received from two former Members of Parliament for transfer of investigation of the case to the Central Bureau of Investigation (CBI). A similar request was also made by Shri Mahapatra's wife and the investigation of the case was ordered to be transferred to the Central Bureau of Investigation (CBI) in November, 1997.

The investigation team of the CBI has so far examined 80 witnesses and the investigation is expected to be completed shortly.

मध्य प्रदेश के लिए परियोजनाओं को स्वीकृति दिया जाना

*143. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगामी वर्षों के लिए सरकार के विचाराधीन योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त परियोजनाओं के वित्त-पोषण हेतु भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदनों/प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है;

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाओं को मध्य प्रदेश में स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना की लागत तथा क्षमता सहित ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन संस्थानों द्वारा मध्य प्रदेश में परियोजना के वित्त-पोषण हेतु अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(च) चयनित स्थलों पर इन परियोजनाओं का कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री के॰ राममूर्ति): (क) फिलहाल सरकार के विचाराधीन मुख्य परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

कंपनी		परियोजना	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)
गैस अथारिटी आफ इंडिया लि॰ (गेल)	(1)	गांधार, गुजरात में गैस संसाधनपरिसर	333
भारत पेट्रोलियम का॰ लि॰ (बी पी सी एल)	(2)	उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में एक रिफ़ाइनरी की स्थापना	6180
मद्रास रिफाइनरी लि॰ (एम आर एल)	(3)	मद्रास, तमिलनाडु में संयुक्त उद्यम विद्युत परियोजना	1300
	(4)	मद्रास रिफाइनरी का विस्तार,तमिलनाडु	2048
कोचीन रिफाइनरी लि॰ (सी आर एल)	(5)	कोचीन रिफाइनरी का विस्तार,केरल	3993
	(6)	कोचीन में 500 मेगावाटक्षमता वाला विद्युत संयंत्र सं॰ उ॰ क॰ के विचाराधीन है	3000
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का॰ लि॰ (एच पी सी एल)	(7)	विशाखापटनम विजयवाड़ा उत्पाद पाइपलाइन को सिकन्दराबाद तक बढ़ाना	345
इंडियन आयल का॰ (आई ओ सी)	(8)	बरौनी रिफाइनरी का विस्तार,बिहार	1744
	(9)	हल्दिया रिफाइनरी, पश्चिम बंगाल में फ्लूडाइज्ड कैटेलिटिक क्रेकिंग इकाई	507
	(10)	गुवाहाटी रिफाइनरी, असम में हाइड्रोट्रीटमेंट सुविधा	483
	(11)	डिग्बोई,असम में डी-वेक्सिंग और डी-आयलिंग इकाई का प्रतिस्थापन	391
	(12)	सावली,गुजरात में 500 मेगावाटक्षमता वाला विद्युत संयंत्र	1670
	(13)	पानीपत, हरियाणा में 254 मेगावाटक्षमता वाला विद्युत संयंत्र	1528
	(14)	दक्षिण भारत में ग्रासरूटरिफाइनरी, तमिलनाडु	7845
	(15)	पैराजाइलीन/पी टी ए, पानीपत, हरियाणा	4056
	(16)	हल्दिया-बरौनी क्रूड पाइपलाइन का आवर्धन	472
	(17)	पश्चिमी तट से कोयाली रिफाइनरी तक क्रूड पाइपलाइन	1105
	(18)	पारादीप, उड़ीसा में पूर्वी भारत रिफाइनरी के लिए विपणन सुविधाएं	818
	(19)	हल्दिया, (चरण-II) प॰ बंगाल में आयात सुविधा	223
	(20)	पानीपत रिफाइनरी, हरियाणा का विस्तार	2348
तेल और प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लि॰ (ओ एन जी सी)	(21)	हजीरा में ग्रासरूट पैराजाइलीन परियोजना	2601
	(22)	सी-22/सी-24 संरचना का विकास-पश्चिमी अपतट	303

(ख) इन परियोजनाओं की वित्तीय बंदी संबंधित तेल कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं के बीच निर्भर करता है।

(ग) और (घ) सरकार ने बीना, मध्य प्रदेश में 6 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता की एक रिफाइनरी की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 5277 करोड़ रुपये है।

(ङ) और (च) इस परियोजना के अक्तूबर, 2002 तक पूरी हो जाने की आशा है। इस परियोजना का इक्विटी ढांचा निम्नानुसार प्रस्तावित है:—

— भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और ओमान आयल कं० लि०, प्रत्येक 26 प्रतिशत (549 करोड़ रुपये)

— तृतीय पक्षकारों सहित जनसाधारण, 48 प्रतिशत (1013 करोड़ रुपये)

— ऋण (3166 करोड़ रुपये)

'दानिक्स' तथा 'दास' अधिकारियों द्वारा हड़ताल

*145. **श्री रामजीलाल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली, अण्डमान और निकोबार आइलैण्ड सिविल सर्विसेज (दानिक्स) तथा दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवाएं (दास) के अधिकारी कब से कब तक हड़ताल पर रहे;

(ख) उनकी मांगें क्या थीं तथा इन मांगों पर केन्द्रीय सरकार का दृष्टिकोण क्या है;

(ग) क्या दिल्ली सरकार ने उक्त अधिकारियों की मांगें माने जाने हेतु अपनी अनुशंसा भेजी है; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय कर लेगी तथा निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि बड़ी संख्या में दानिक्स और कुछ दास अधिकारी 24.9.1998 से 9.10.1998 तक की अवधि के दौरान कभी-कभी ड्यूटी पर नहीं आए।

(ख) दानिक्स अधिकारी सेवा के एन्ट्री ग्रेड 2000-3500 रु० (संशोधन पूर्व) को 2200-4000 रु० (संशोधन पूर्व) में बढ़ाए जाने और 4500-5700 रुपए (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में उच्चतम पद पर नया ग्रेड शुरू करने के बारे में पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन की मांग कर रहे हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने इस सेवा के वेतन और ग्रेड संरचना के बारे में पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने की अनुशंसा की है।

(घ) मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और इस बारे में अन्तिम निर्णय शीघ्र लिए जाने की संभावना है।

Private Investment for Development of Tourism in North-East

*148. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that the North-Eastern region can be converted into a tourist paradise, if properly planned and developed;

(b) whether Government have any time-bound scheme for creation of tourist spots in the region;

(c) if so, the location of spots identified and the amount earmarked thereon; and

(d) the details of programmes and procedure finalised to attract private investment for developing tourist resorts in the North-Eastern region and achievement made, so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI OMAK APANG): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Identification and development of Tourist Spots is primarily the responsibility of the State Governments. However, Ministry of Tourism extends Central Financial Assistance for creation of Tourist Infrastructure to the State Governments on receipt of specific project proposals their inter se priority and availability of funds.

The Ministry of Tourism constituted a Task Force to study the special problems of the North East Region and draw up specific schemes and projects for the development of tourism. The Task Force in its Report has identified major tourist centres in the region for tourism development in consultation with the State Governments. The Report has recommended upgradation of Guwahati Airport with